

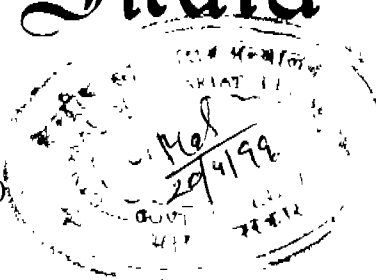


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 73]
No. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1999/माघ 21, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1999/MAGHA 21, 1920

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 94(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति, के०आर० नारायणन को गोवा राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान {जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है} के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है,

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं:

{क} उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ,

{ख} घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी, और

॥ग॥ निम्नलिखित आनुवंशिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:

॥१॥ इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड॥क॥ के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा,

॥११॥ उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात्:

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेश करने से है,

अनुच्छेद 151 के खण्ड॥2॥ का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

अनुच्छेद 163 और 164,

अनुच्छेद 166 के खण्ड॥3॥ का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच आबंटन से है,

अनुच्छेद 167

अनुच्छेद 169 के खण्ड॥१॥ का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है,

अनुच्छेद 174 का खण्ड॥१॥ और खण्ड॥2॥ का उपखण्ड॥क॥,

अनुच्छेद 175 से 178 तक ॥जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं॥,

अनुच्छेद 179 का खण्ड॥ख॥ और ॥ग॥ और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक,

अनुच्छेद 180 और 181,

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से है,

अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196,

अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खण्ड ॥3॥ और खण्ड ॥4॥,

अनुच्छेद 202 के खण्ड ३ का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से है,

अनुच्छेद 208 से 211 तक जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं,

अनुच्छेद 213 के खण्ड 1 का परन्तुक और खण्ड 3 का परन्तुक, और

अनुच्छेद 323 के खण्ड 2 का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

॥ 11 ॥ उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा भंग की जाती है,

॥ 1 V ॥ विधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा,

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड 1 के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी,

॥ 1 V ॥ संविधान में राज्य के विधान मण्डल के या एतद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्धोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड 1 के उपखण्ड क में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और गोवा दमन एवं दीव साधारण खण्ड अधिनियम 1965 गोवा 1965 का अधिनियम 7 जिस रूप में गोवा राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 1897 का 10वें का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली,

दिनांक 10 फरवरी, 1999

(के. आर. नारायणन)

राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

दिनांक 10 फरवरी, 1999

[फा. सं. V/11013/9/98-सी. एस. आर.]

बी. पी. सिंह, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 1999

G.S.R. 94(E).—The following Proclamation by the President is published for general information

Whereas, I, K.R.Narayanan, President of India, have received reports from the Governor of the State of Goa and after considering the reports and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State can not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I -

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of

this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

- (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:-

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198; and clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State, shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State, shall be construed as references to the President and

respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and X article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Goa, Daman and Diu General Clauses Act, 1965 (No. 7 of 1965), as in force in the State of Goa, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi,

Dated, the 10th February, 1999

New Delhi,

Dated, the 10th February, 1999

(K.R. NARAYANAN)

President

[F No. V/11013/9/98-CSR]

B.P Singh, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 95(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 11 2 1999 मे देसवे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि गोवा राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,

दिनांक 10 फरवरी, 1999

(के. आर. नारायणन)

राष्ट्रपति

[फा. सं. V/11013/9/98-सी. एस. आर.]

नई दिल्ली,

दिनांक 10 फरवरी, 1999

बी. पी. सिंह, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1999

G.S.R. 95(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 11 2 1999 day of February, 1999 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Goa and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,

Dated, the 10th February, 1999

(K.R. NARAYANAN)

President

[F. No. V/11013/9/98-CSR]

B.P. Singh, Home Secy.

New Delhi,

Dated, the 10th February, 1999